भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4376

28 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए नियत

"इलेक्ट्रिक वाहनों की वार्षिक बिक्री"

4376. श्री के. मुरलीधरन:

श्री एंटो एन्टोनी:

डॉ. अमर सिंह:

श्री टी.एन. प्रथापन:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की वार्षिक बिक्री का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में कहा गया है कि भारत अगले सात वर्षों के भीतर एक करोड़ इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन के अपने लक्ष्य को पूरा करने के मार्ग पर है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है: और

(ग) सरकार के इस अनुमान के आलोक में कि भारत को 50 GWH की लिथियम-आयन सेल और बैटरी विनिर्माण संयंत्रों की स्थापना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 33,750 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता है, सरकार द्वारा निकट भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन प्रक्रियाओं में लागत में कमी लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क) : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के ई-वाहन पोर्टल के अनुसार पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	**कुल संख्या**
2018	1,29,125
2019	1,65,461
2020	1,23,092
2021	3,27,976
2022	10,15,196
2023 (15-03-2023 तक)	2,56,980
कुल योग	**21,64,353**

(ख) : भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) : सरकार ने भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 50 गीगावाट घंटा की विनिर्माण क्षमता प्राप्त करने के प्रयोजन से 'उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण' संबंधी उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम 12 मई, 2021 को अनुमोदित की है जिसका बजटीय परिव्यय 18,100 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त, 5 गीगावाट घंटे की उत्कृष्ट एसीसी प्रौद्योगिकियों को भी इस स्कीम के अंतर्गत शामिल किया गया है।

पीएलआई एसीसी स्कीम के अंतर्गत तीन इकाइयों को एसीसी क्षमताएं सौंपी गयी हैं- अर्थात् राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (5 गीगावाट घंटा), ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड (20 गीगावाट घंटा) और रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड (5 गीगावाट घंटा)।

*****